प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत
सरकार के जल संसाधन मंत्रालय

06-जून-2018 14:17 IST

विश्व बैंक रु। 6,000 करोड़ अटल भुजल योजना

विश्व बैंक ने जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय की 6000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना, अटल भुजल योजना (एबीएचवाई) को मंजूरी दे दी है। इस योजना को विश्व बैंक सहायता के साथ 2018-19 से 2022-23 तक पांच साल की अवधि में लागू किया जाना है। योजना प्रस्ताव को पहले से ही व्यय वित्त समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है और मंत्रालय जल्द ही परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगेगा।

देश के एक बड़े हिस्से में भूजल संसाधनों की गंभीरता को संबोधित करने के लिए मंत्रालय द्वारा अटल भुजल योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य समुदाय भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिक क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। योजना के तहत पहचाने गए प्राथमिक क्षेत्रों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में गिरावट आई है। ये राज्य भारत में भूजल के संदर्भ में अत्यधिक शोषित, महत्वपूर्ण और अर्ध-महत्वपूर्ण ब्लॉक की कुल संख्या का लगभग 25% प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारत में पाए जाने वाले दो प्रमुख प्रकार के भूजल प्रणालियों को भी कवर करते हैं - जलोढ़ और हार्ड रॉक एक्वाइफर्स- और भूजल प्रबंधन में संस्थागत तैयारी और अनुभव की अलग-अलग डिग्री हैं।

इस योजना के तहत निधि राज्यों को भूजल प्रशासन के लिए जिम्मेदार संस्थानों को मजबूत करने के साथ-साथ भूमि के संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्यों में मान्यता प्राप्त प्राथमिक क्षेत्रों में उनके केंद्रित कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करके राज्यों में चल रही सरकारी योजनाओं के अभिसरण की सुविधा प्रदान करेगी। इस राज्य के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ पहुंचाने की योजना से कार्यान्वयन की उम्मीद है। इस योजना के तहत निधि भाग लेने वाले राज्यों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

भूजल प्रबंधन में सक्रिय समुदाय भागीदारी सुनिश्चित करना योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस योजना में विभिन्न प्रयोजनों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी जैसे कि जल प्रयोक्ता संघों का गठन, ग्राउंड वॉटर डेटा की निगरानी और प्रसार, ग्राम पंचायत वार जल सुरक्षा योजनाओं और टिकाऊ भूजल प्रबंधन से संबंधित आईईसी गतिविधियों के कार्यान्वयन और प्रसार को प्रसारित किया गया है। सामुदायिक भागीदारी से सार्वजनिक वित्तपोषण की प्रभावशीलता में सुधार करने और भाग लेने वाले s0tates में भूजल पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को संरेखित करने के लिए नीचे की भूजल योजना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की भी उम्मीद है ।

The implementation of the scheme is expected to have several positive outcomes like better understanding of the ground water regime, focused and integrated community based approach for addressing issues related to ground water depletion, sustainable ground water management through convergence of on-going and new schemes, adoption of efficient water use practices to reduce ground water use for irrigation and augmentation of ground water resources in targeted areas.

*****

NP/SKP/IA